

प्रेषक,

अमित सिंह नेगी,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा मे.

प्रमुख अभियन्ता,
लोक निर्माण विभाग,
देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग-२

विषय:-

जनपद देहरादून में विकासखण्ड-डोईवाला में विभिन्न ०२ कार्यों की प्रथम चरण की प्रशासकीय एवं वित्तीय तथा व्यय की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मुख्य अभियन्ता ग०क्षे०, लोक निर्माण विभाग पौड़ी द्वारा जनपद देहरादून में विकासखण्ड-डोईवाला में प्रथम चरण की स्वीकृति हेतु संलग्न विवरणानुसार उपलब्ध कराये गये प्रारम्भिक आगणन, जिसकी लागत ₹ 50.32 लाख है, पर ₹०१००००००० वित्त द्वारा औचित्यपूर्ण पाई गई धनराशि ₹ 32.68 लाख [₹ 15.68 + ₹ 17.00 उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली से कराये जाने वाले कार्य] की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए चालू वित्तीय वर्ष २०१३-१४ में व्यय हेतु प्रति कार्य ₹ ०.१० लाख अर्थात् कुल ०२ कार्य हेतु ₹ ०.२० लाख (₹ बीस हजार मात्र) की अनुमति, महामहिम श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(i)- उक्त स्वीकृति के आधार पर विभाग द्वारा समस्त प्रक्रियात्मक कार्यों को समयबद्ध रूप से पूर्ण किया जायेगा तदोपरान्त शासनादेश सं०:-१७६४ / ११(२) / १०-१७(सामान्य) / २००८ दिनांक १७ जून, २०१० की व्यवस्थानुसार विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर शासन को वित्तीय स्वीकृति हेतु प्रस्तुत की जायेगी। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट पर शासन से अनुमोदन प्राप्त होने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(ii)- आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को जो दरें शैडयूल आफ रेट में स्वीकृत नहीं हैं, अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति पर नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।

(iii)- कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना की स्वीकृत नाम है, स्वीकृत नाम से अधिक व्यय कदापि न किया जाय। यदि प्रथम चरण हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि में बचत हो रही है तो उसका समायोजन विस्तृत आगणन तैयार करते समय किया जायेगा।

(iv)- कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टयों के अनुरूप ही कार्यों को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें।

(v)- आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है व्यय उसी मद में किया जाय, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।

(vi)- स्वीकृत किया जाने वाला कार्य उत्तराखण्ड प्रोक्यौरमेन्ट रूल्स-२००८ एवं उक्त के विषय में समय-समय पर निर्गत समस्त दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा। इसके अतिरिक्त बजट मैनुअल के निर्देशों का भी अनुपालन किया जायेगा।

(vii)- मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं०:- २०४७ / XIV-२१९(२००६) दिनांक ३०-०५-२००६ द्वारा निर्गत आदेशों का कार्य कराते समय या आगणन गठित करते समय कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(viii)- उक्तानुसार स्वीकृत आगणनों में एन०पी०वी०, भूमि अधिग्रहण, यूटिलिटी शिपिटंग आदि मदों के सम्बन्ध में यथावश्यक व्यय अनुदान सं०-२२-लेखाषीर्क-५०५४ सङ्कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-०४ जिला तथा अन्य सङ्कों- आयोजनागत-८००-अन्य व्यय-०५-सङ्क/भवन/सेतु आदि हेतु भूमि अधिग्रहण -००-२४ वृहत निर्माण कार्य में विभागीय आय-व्ययक में प्राविधानित निवर्तन पर रखी गयी धनराशि से किया जायेगा।

देहरादून: दिनांक:

१० जून

मई, २०१३

(ix)– स्वीकृत किये जा रहे कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता का सम्पूर्ण दायित्व संबंधित अधिशासी अभियन्ता का होगा।

(x)– वर्तमान में व्यय हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय 31-03-2014 तक सुनिश्चित किया जायेगा। यदि स्वीकृत कार्य के सापेक्ष चालू वित्तीय वर्ष में अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता होती है तो उसका व्यय संगत मद में निवर्तन में रखी गई धनराशि से नियमानुसार किया जायेगा।

(xi) यदि स्वीकृत किये जा रहे कार्यों में से कोई कार्य अथवा उसका कोई भाग प्रधानमंत्री ग्रामीण सङ्क प्रोजेक्ट अन्तर्गत स्वीकृत है अथवा प्रधानमंत्री ग्रामीण सङ्क प्रोजेक्ट के अन्तर्गत स्वीकृत की जा सकती है, तो ऐसे कार्य की स्वीकृति खतः निरस्त समझी जायेगी।

(xii)– उक्त कार्य हेतु वित्तीय वर्ष 2013-14 में व्यय हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि ₹ 0.20 लाख का बजट आबंटन, वित्त अनुभाग-1 के शासनादेश सं0-183/XXVII(1)/2012 दिनांक 28 मार्च, 2012 के अनुक्रम में, लोक निर्माण विभाग के अनुदान सं0-22, के अन्तर्गत अलॉटमेन्ट आई0डी0 सं0:- S1306220351 द्वारा आपको आबंटित कोड सं0- 4227 Chief Engineer PWD में कर दिया गया है।

(2) इस संबंध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2013-14 में लोक निर्माण विभाग के अनुदान सं0-22-लेखाषीर्शक-5054 सङ्कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-04 जिला तथा अन्य सङ्कों -आयोजनागत -800-अन्य व्यय-03 राज्य सेक्टर-02 नया निर्माण कार्य-24 बहुत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

(3) यह आदेश वित्त अनुभाग-2 के अशासकीय संख्या- 142/XXVII(2)/2013 दिनांक 07 जून, 2013 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक:— यथोपरि।

भवदीय,

(अमित सिंह नेगी)
अपर सचिव

संख्या:— 3161 (1) / 111(2) / 13-04(प्रा0आ0) / 2011 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार (लेखा प्रथम), ओबराय मोर्टस बिल्डिंग, माजरा देहरादून।
2. आयुक्त गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
3. जिलाधिकारी, देहरादून।
4. मुख्य अभियन्ता, ग0क्षे0, लो.नि.वि., पौड़ी।
5. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी देहरादून।
6. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. वित्त अनुभाग-2/वित्त नियोजन प्रकोष्ठ/राज्य योजना आयोग उत्तराखण्ड शासन।
8. अधीक्षण अभियन्ता, नवम् वृत्त, लो0नि0वि0, देहरादून।
9. अधिशासी अभियन्ता, अस्थाई खण्ड, लो0नि0वि0, ऋषिकेश।
10. गार्ड बुक।

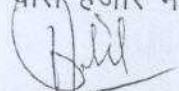
आज्ञा से,

(धीरेन्द्र सिंह दत्ताल)
उप सचिव

शासनादेश संख्या:- 3161 (1)/ 111(2)/ 13-04(प्रा०आ०) / 2013 दिनांक 10 जून, 2013 का संलग्नक

क्र० सं०	कार्य का नाम	लम्बाई किमी० में	टी०ए०सी० द्वारा अनुमोदित लागत	(धनराशि लाख ₹ में) चालू वित्तीय वर्ष में व्यय हेतु अवमुक्त धनराशि
1	जनपद देहरादून में भानियावाला से ऋषिकेश मार्ग पर भानियावाला से रानीपोखरी (डांडी) तक (एयरपोर्ट के समीप) दो लेन मार्ग का चार लेन में परिवर्तन।	8.80	14.08	0.10
2	जनपद देहरादून में ऋषिकेश डोईवाला मोटर मार्ग के किमी० 16 से जौलीग्रान्ट एयरपोर्ट के टर्मिनल भवन की एप्रोच हेतु दो लेन मार्ग का चार लेन में विस्तारीकरण।	1.00	18.60 [₹ 1.60 + ₹ 17.00 उत्तराखण्ड धिप्राप्ति नियमावली से कराये जाने वाले कार्य]	0.10
	योग:-	9.80	32.68 [₹ 15.68 + ₹ 17.00 उत्तराखण्ड धिप्राप्ति नियमावली से कराये जाने वाले कार्य)	0.20

(कुल ₹ बीस हजार मात्र)


(धीरेन्द्र सिंह दत्ताल)
उप सचिव